जल स्त्रोतों के रिचार्जिंग सिस्टम को बढ़ाएं

पंचायत मंत्री पटेल ने जल, भूमि संरक्षण के प्रयास धरातल पर उतारने दिया जोर

भोपाल, 7 जुलाई. पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि हमें जल, भूमि संरक्षण के लिये अभी से ठोस प्रयास करने होंगे. जल स्त्रोतों के रिचार्जिंग सिस्टम को बढ़ाना होगा. फसलों का चक्रीकरण और पौधरोपण में वैज्ञानिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना होगा.

मंत्री पटेल सोमवार को राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन की साधारण सभा की बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने बैठक में चिंता करते हुए कहा कि बढ़ती जनसंख्या के कारण जल स्त्रोतों के रिचार्जिंग सिस्टम धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे हैं. नदियों के उद्गम स्थलों का संरक्षण नहीं करने के कारण उनके स्त्रोत सूखते जा रहे हैं. मरूस्थलीकरण की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है. इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह, प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव पीएचई पी. नरहरि सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.

मंत्री पटेल ने कहा कि राजीव गांधी जल संग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के अंतर्गत विभिन्न विभागों से मिशन के परिणामों की जानकारी प्राप्त की जाए. उन्होंने कहा कि मिशन के तहत सभी परियोजनाओं का थीमेटिव विश्लेषण किया जाये. मंत्री पटेल ने कहा कि वॉटर शेड परियोजनाओं के बेहतर परिणामों के लिये एनजीओ को संबद्ध करने की नीति तैयार की जाये. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की प्रगति का आंकलन जमीनी स्तर पर करें. मंत्री पटेल ने कहा कि वॉटर शेड परियोजनाओं के अंतर्गत क्लस्टर आधारित सब्जी उत्पादन का कार्य अच्छा करने वाले जिलों का स्वयं भ्रमण करेंगे. इस अवसर पर चंदेला-बुंदेला तालाबों का जीर्णोद्धार कार्यशाला प्रतिवेदन की पुस्तिका का विमोचन भी किया गया.

> मिशन संचालक अवि प्रसाद ने बैठक में साधारण सभा के समक्ष विभिन्न एजेंडा प्रस्तुत किये. उन्होंने पीएमकेएसवाय 2.0 की प्रगति, वॉटर शेड परियोजनाओं का सोशल ऑडिट, परियोजना के प्रभावों का विश्लेषण, मिशन के संस्थागत सुदृढ़ीकरण, जीआईएस एवं एआई सुविधा विकसित करने आदि विषयों के संबंध में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मिशन के तहत वॉटर शेड परियोजनाओं के निरीक्षण के लिये एरिया ऑफिसर मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा रहा है. उन्होंने वॉटर शेड वर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की जानकारी भी दी.

घाट निर्माण के लिए जगह नहीं मिल पा रही सपाट

- 29 किलोमीटर घाट निर्माण का कार्य हो रहा है बाधित
- बारिश की वजह से मौके पर आ रही दिक्कतें
- 31 मई को मुख्यमंत्री डॉ यादव ने किया था भूमि पूजन

29 किलोमीटर इस तरह बनाया जाना प्रस्तावित है

घाट- नदी किनारे मौके पर इस तरह हो रहे हालात

नवभारत न्यूज

उज्जैन. आखिर वही हुआ जिसका डर था, बरसात की वजह से 29 किलोमीटर घाट निर्माण बाधित हो रहा है, जल संसाधन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से लेकर ठेकेदार को मौके पर समस्या आ रही है, जिस दिन बारिश होती है उसे दिन काम नहीं हो पाता है ऐसे में कच्ची जगह का काम जल्द खत्म करने के लिए बारिश थमने का इंतजार करना पड़ रहा है.

स्नान और महाकाल दर्शन इन दोनों प्रकल्प पर ही महाकुंभ 2028 का पूरा दारोमदार है, कि श्रद्धालुओं के स्नान की व्यवस्था मोक्षदायिनी माँ क्षिप्रा के घाट पर बेहतर ढंग से हो जाए और उसके बाद बाबा महाकाल के दर्शन कर संतों से भेंट हो जाए, ऐसे में 29 किलोमीटर घाट निर्माण के लिए मुख्यमंत्री डॉ यादव ने भूमि पूजन किया था, तब से लेकर अब तक जल संसाधन विभाग मिट्टी -गिट्टी में उलझा हुआ है. नवभारत से चर्चा में जल संसाधन विभाग के एसडीओ मयंक परमार ने बताया कि 29 किलोमीटर लंबे घाट जल्द ही बनाया जाना है, इसके लिए त्रिवेणी घाट शनि मंदिर के समीप से निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है जो आगे तक किया जाना है हाल फिलहाल बारिश की वजह से कुछ दिक्कते हो रही है बावजूद इसके मौके पर कार्य जारी है.

अभी यह है पोजीशन

जल संसाधन विभाग कि पीआईयू विंग यहां पर 29 किलोमीटर घाट का निर्माण जिस प्रकार से करवा रही है, ऐसे में अर्थ वर्क अभी चल रहा है, डाउनस्ट्रीम पर काम होना है, जिसमें 4-5 स्थानों पर ही अभी काम शुरू हो पाया है. 29 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर तक कार्य पहुंचा है. मिट्टी का काम पूरा होने के बाद सीमेंट कंक्रीट वर्क किया जाएगा. क्षिप्रा नदी में पानी के बहाव के साथ ही लगातार बारिश की वजह से काम की गति धीमी है.

> **21 बैराज का भी निर्माण**
> कुंभ में जो श्रद्धालु घाट पर स्नान, पूजा के लिए आएंगे, ऐसे में प्लेटफार्म, सीढ़ियाँ और लोवर लैंडिंग प्लेटफार्म बनाए जाएंगे. साथ ही 21 बैराज, स्टॉपडैम और वेंटेड काजवे निर्माण भी किए जाएंगे.

परियोजना की लागत 864 करोड़

उज्जैन में 29 किलोमीटर लंबे घाट का निर्माण क्षिप्रा नदी के तट पर किया जा रहा है. यह घाट सिंहस्थ 2028 की तैयारियों का हिस्सा हैं और इसका उद्देश्य शिप्रा नदी के तट को विकसित करना है. परियोजना की लागत 864 करोड़ है.

प्रधानमंत्री के कहने पर सीएम ने किया भूमि पूजन

उज्जैन अंगारेश्वर महादेव मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 31 मई को 29 किलोमीटर लंबे घाट का भूमि पूजन किया था, पहले इसका भूमि पूजन प्रधानमंत्री करने वाले थे, जब भोपाल में कार्यक्रम हो रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री डॉ यादव कहा कि उक्त योजना का भूमि पूजन उज्जैन जाकर आपको ही करना चाहिए, ऐसे में डॉ यादव द्वारा ये सौगात दी गई.

एक नजर में

सीएम ने विधायक पटवा की माता से लिया आशीर्वाद

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की धर्मपत्नी फूल कुंवर पटवा के 95वें जन्म दिवस पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विधायक सुरेंद्र पटवा के 74 बंगला स्थित निवास पहुंचकर फूल कुंवर पटवा को पुष्पगुच्छ और शाल-श्रीफल भेंट किया तथा पटवा के स्वस्थ-सुखी जीवन और दीर्घायु होने की कामना की. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर आयोजित सुंदरकांड पाठ के लिए दीप प्रज्जवलित किया.

श्रद्धालुओं की कार हादसे का शिकार, तीन की मौत

शहडोल. शहडोल जिले में उत्तरप्रदेश से छत्तीसगढ़ जा रहे श्रद्धालुओं की कार आज तड़के हादसे का शिकार हो गई, जिससे तीन महिला यात्रियों की मौत हो गई. ब्योहारी पुलिस सूत्रों ने बताया कि जोरा गांव के पास आज तड़के चार बजे रीवा-अमरकण्टक राजमार्ग पर एक कार के सड़क किनारे वृक्ष से टकराने से 3 महिला यात्रियों गायत्री कँवर, मालती पटेल और इन्दिरा बाई की मौत हो गई. वहीं चार गंभीर घायलों को ब्योहारी अस्पताल ने शहडोल मेडिकल कॉलेज रेफर किया है. यात्री अयोध्या से तीर्थाटन कर वापस छत्तीसगढ़ जा रहे थे.

कॉलेजों में स्नातकोत्तर के प्रवेश के लिए तिथि में वृद्धि

भोपाल. उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2025-26 में, महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए तिथि में वृद्धि की है. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्नातकोत्तर स्तर (पीजी) सत्र 2025-26 में ऑनलाइन प्रवेश अंतर्गत सीएलसी चरण के लिए अद्यतन समय सारणी जारी की गई है. सत्र 2025-26 में स्नातकोत्तर कक्षाओं में मेजर माइनर विषयों में एवं मेजर एवं माइनर विषय के अतिरिक्त अन्य विषय में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थी, 7 से 10 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीयन, आवेदन कर सकेंगे.

भैंस चराते वक्त भालू ने नोंच-नोंचकर 3 को मार डाला

सीधी, 7 जुलाई. जिले के संजय टाइगर रिजर्व के बस्तुआ रेंज में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया.

जंगल में भैंस चरा रहे गांव वालों पर एक जंगली भालू ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें 2 गांव वालों की मौके पर ही, जबकि एक की रास्ते में मौत हो गई. वहीं, 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके बाद

गुस्साए लोगों ने भालू को पीट-पीटकर मार दिया. इलाके में दहशत का माहौल है. सीधी जिले के संजय टाइगर रिजर्व के बस्तुआ रेंज इलाके में कुछ गांव वाले रोज की तरह सोमवार को भी भैंसें चराने के लिए गए थे. इस बीच उन पर अचानक से एक जंगली भालू ने हमला कर दिया. भालू को देखते ही लोगों ने भागकर जान बचाने को कोशिश की, लेकिन तीन लोगों की इस दौरान हमले में मौके पर ही मौत हो गई. जबकि 4 लोग घायल हो गए. मृतकों की पहचान बब्बू यादव, दीनबन्धु साहू और संतोष यादव के रूप में हुई है.

> हमले की जांच में जुटा वन विभाग घटना की सूचना मिलते ही मारवास पुलिस स्टेशन के थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंच गए. मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मौके पर सांसद डॉ राजेश मिश्रा और कुसमी विधायक कुंअर सिंह टेकाम पहुंचे और परिवारजनों को सांत्वना दी.

मूसलाधार बारिश को लेकर आरेंज अलर्ट जारी

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 7 जुलाई. मप्र के नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, पाढ़र्णा और बालाघाट जिलों में मंगलवार को भारी बारिश हो सकती है. बारिश की संभावना को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है. इन जिलों में मूसलाधार बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने आरेंज अलर्ट जारी किया है.

इस दौरान 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी. इसके साथ ही शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, श्योरपुरकलां, ग्वालियर, दतिया, कटनी, विदिशा, राजगढ़, टीकमगढ़, शाजापुर और छतरपुर सहित

11 जुलाई तक जारी रहेगा बारिश का दौर | 40 किमी की रफ्तार से चलेगी हवा

जिलों में भी गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. प्रदेश में फिलहाल 11 जुलाई तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना पूर्व में जताई गई है.

मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में, मानसून ट्रफ़ माध्य समुद्र तल पर श्री गंगानगर, सिरसा, मेरठ, वाराणसी, डाल्टनगंज, पुरुलिया, दक्षिण-पश्चिम गंगीय पश्चिम बंगाल और निकटवर्ती क्षेत्रो में बने कम दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र से होकर पूर्व-दक्षिण-पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्व तक विस्तृत है.

दक्षिण-पश्चिम गंगीय पश्चिम बंगाल और निकटवर्ती क्षेत्रो में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इससे जुड़ा चक्रवातीय परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 7.6 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है एवं ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है.

> मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान इसके झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ से होते हुए धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है. एक ट्रफ़ दक्षिणी राजस्थान से, मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ एवं दक्षिणी झारखंड होकर दक्षिण-पश्चिमी गंगीय पश्चिम बंगाल और निकटवर्ती क्षेत्रों में बने निम्न दबाव क्षेत्र से जुड़े चक्रवातीय परिसंचरण तक माध्य समुद्र तल से 3.1 किमी और 7.6 किमी की ऊंचाई के मध्य विस्तृत है एवं ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुकी हुई है.

नाले में बही कार, पति पत्नी व दो बच्चों की मौत

- मंत्री ने की आर्थिक सहायता की घोषणा
- पूरा परिवार उजड़ गया, मां-बाप पर टूटा दुखों का पहाड़

नवभारत

अनूपपुर, 7 जुलाई. रविवार की रात अनूपपुर जिले में अमरकंटक रोड पर एक हृदयविदारक हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की जान चली गई. जिला मुख्यालय से 10 किमी दूर सजहा नाले में तेज बहाव के दौरान एक कार बह गई, जिसमें पति-पत्नी और उनके दो मासूम बच्चे सवार थे. सोमवार को पुलिस ने चारों के शव बरामद कर लिए हैं.

एसईसीएल सोहागरपुर के फोरमैन चंद्रशेखर यादव 38 वर्ष, अपनी पत्नी प्रीति यादव 37 वर्ष, पुत्र रेयांश 8 वर्ष और पुत्री सीबी 2 वर्ष के साथ अमरकंटक से लौट रहे थे. हादसा रविवार शाम करीब 7 बजे हुआ, जब सजहा पुल पर तेज बहाव के बावजूद उन्होंने कार आगे बढ़ाई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्थानीय लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन एक बस के पार होने के बाद चंद्रशेखर ने भी कार आगे बढ़ा दी. पुल का हिस्सा अचानक टूट गया और कार तेज धारा में बह गई.

इंदौर में 11 को मप्र ग्रोथ कॉन्क्लेव

भोपाल, 7 जुलाई. प्रदेश में रीयल एस्टेट की गतिविधियों के विस्तार के लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा 11 जुलाई को इंदौर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है. नेक्स्ट होराइजन- बिल्डिंग सिटीज़ ऑफ टुमारो थीम पर आधारित यह कॉन्क्लेव राज्य के शहरी विकास और निवेश के लिये नए क्षितिज खोलने का माध्यम बनेगा. उद्योग एवं रोजगार वर्ष 2025 के अंतर्गत इस आयोजन का उद्देश्य प्रदेश की नगरीय अधोसंरचना को भविष्योन्मुखी बनाना, सतत विकास को गति देना और व्यापक निवेश आकर्षित करना है.

बिल्डिंग सिटीज़ ऑफ टुमारो थीम पर कॉन्क्लेव

निवेश को साकार करने सुदृढ़ इको-सिस्टम

मध्यप्रदेश देश के केन्द्र में रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण महत्वपूर्ण स्थान रखता है. इसलिये यहां से आसानी से देश भर से लॉजिस्टिक संपर्क किया जा सकता है. प्रदेश में तेज गति से होता शहरीकरण, विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन जैसे शहरों में सशक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है. राज्य में सस्ती भूमि और श्रम, सरल प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं और उद्योगों के लिए अनुकूल नीतियाँ लागू की गई हैं. मध्यप्रदेश में केन्द सरकार की प्रधानमंत्री गति-शक्ति, अमृत 2.0 और स्मार्ट-सिटी जैसी योजनाओं से प्रदेश में समावेशी विकास हो रहा है.

> प्रदेश में विकास और निवेश शहरी परिवहन (मेट्रो, ई-बस, मल्टीमॉडल हब), किफायती आवास, स्लम पुनर्विकास, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, जलापूर्ति, सीवेज नेटवर्क, झील संरक्षण, डिजिटलीकरण, ई-गवर्नेंस, भवन स्वीकृति प्रणाली और स्वच्छ ऊर्जा, हरित भवन, रिन्यूएबल इनफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है.

देश में मसाला उत्पादन में मध्यप्रदेश प्रथम

मंत्री कुशवाहा ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बैठक में गिनाई उपलब्धियां

भोपाल, 7 जुलाई. उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा सोमवार को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 96वीं आमसभा बैठक में सम्मिलित हुए. भारत रत्न सी. सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम एमएएससी कॉम्पलेक्स के सभागार में आमसभा की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की.

मंत्री कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश को उद्यानिकी राज्य में विकसित करने के लिये सरकार

दृढ़ संकल्पित है. मध्यप्रदेश का मसालों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है. उन्होंने कहा कि इसको दृष्टिगत रखते हुये भारत कृषि अनुसंधान परिषद का प्रदेश में अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जाये. इससे प्रदेश के कृषकों को मसाला फसलों की उन्नत प्रजातियां सुलभ एवं उचित दाम पर उपलब्ध हो सकेंगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मसाला उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा. कृषकों की आय में वृद्धि, उद्यानिकी उत्पाद के मूल्य संवर्धन से प्र-संस्करण उद्योग को बढ़ावा, प्रदेश एवं देश के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय के अध्ययन में सुविधायें प्राप्त होगी तथा प्रदेश के उद्यानिकी उत्पाद को निर्यात प्रोत्साहन मिलेगा.

> मंत्री कुशवाहा ने कहा कि सब्जियों की संकर किस्मों के बीज बाजार में अधिक कीमतों में उपलब्ध हो पाते है. भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा उत्पादित संकर सब्जी बीजों को प्रदेश के कृषकों को सुलभ एवं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर बीज उत्पादन का कार्यक्रम अभियान के रूप में चलाया जाए. इससे कम लागत और कम समय में किसान बेहतर उत्पादन कर सकेंगे. आम सभा की बैठक में अनुसंधान परिषद के कार्यों का लेखा-जोखा तथा भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा की गई.

एक नजर में

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को वांछित प्रारूप शीघ्रतापूर्वक जारी कर देना चाहिये

आयकर विवरणी के प्रारुप वेबसाईट पर अपलोड नहीं होने से लाखों करदाता परेशान

इंदौर. आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए करदाताओं को 15 सितम्बर 2025 तक आयकर विवरणी एवं ऑडिट की पात्रता वाले करदाताओं को 30 सितम्बर 2025 तक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है किंतु वित वर्ष की समाप्ति के लगभग सवा तीन माह बाद भी अभी तक आयकर विभाग द्वारा विवरणीयों के सारे प्रारूप एवं ऑडिट प्रारूप ई-फाईलिंग वेबसाईट पर अपलोड नहीं किए गए है. जिससे देश के लाखो करदाता अभी तक अपनी विवरणीयां प्रस्तुत नही कर पा रहे है.

यह बात वरिष्ठ कर सलाहकार बीएल जैन ने कही. श्री जैन ने बताया कि नियमानुसार केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को 1 अप्रैल को ही आयकर विवरणी के प्रारूप ई-फाइलिंग वेबसाईट पर अपलोड कर देना चाहिए ताकि करदाता

अपनी विवरणी निर्धारित समय पर दाखिल कर सकें. विभागीय व्यवस्था के तहत् विभिन्न श्रेणी के करदाताओं के लिए अलग-अलग प्रारूप आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक वित वर्ष के लिए जारी किए जाते है इस मर्तबा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा केवल प्रारूप 1 एवं 4 ही जारी किए गए है जो वेतन भोगी कर्मचारियों एवं अन्य स्त्रोत से आय प्राप्तकर्ता एवं आयकर अधिनियम की धारा 44-एडी, एई के तहत् आय दर्शाने वाले करदाताओं के लिए लागू होता है. लेकिन व्यवसाय से होने वाली आय एवं भागीदारी फर्म तथा कंपनी करदाताओं के लिए वांछित प्रारूप 2, 3, 5 एवं 7 तथा ऑडिट का प्रारूप भी अभी तक केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा ई-फाईलिंग वेबसाईट पर अपलोड नहीं किया गया होने के कारण इस श्रेणी के करदाता अपनी विवरणी जमा नही करवा पा रहे है. अनेक करदाताओं को बैंक लोन सहित अन्य कार्यो के लिए वित वर्ष 2024-25 की विवरणी तथा ऑडिट रिपोर्ट की अनिवार्यता होती है लेकिन अभी तक प्रारूप जारी नहीं होने के कारण करदाताओं के कार्य रूके हुए हैं.

शीघ्र जारी करना चाहिए प्रारूप

यदि करदाता समय पर विवरणी नहीं जमा करवा पाता है तो उसे नियमानुसार पेनल्टी का भुगतान करना होगा. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से किए जा रहे विलंब का खामियाजा देश के लाखो करदाताओं को अनावश्यक रूप से उठाना पड़ेगा. ऐसी स्थिति में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को वांछित प्रारूप शीघ्रतापूर्वक जारी कर देना चाहिये तथा आगामी वित्तीय वर्षों के लिए भी 1 अप्रैल के पूर्व वांछित प्रारूप ई-फाईलिंग वेबसाईट पर अपलोड कर देना चाहिये क्योंकि सीबीडीटी के पास तो पूरा एक वर्ष का समय होता है.

कम समय कारण होगी परेशानी

आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत् जिन करदाताओं को ऑडिट की पात्रता नही आती है उन्हें 31 जुलाई 2025 तक विवरणी प्रस्तुत करना होती है लेकिन वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा इस तिथी को आगे बढाया जाकर 15 सितम्बर 2025 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है. साथ ही ऑडिट की पात्रता वाले करदाताओं को 30 सितम्बर 2025 तक ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है. इन तिथियों के पश्चात् विवरणी जमा करने अथवा आडिट करवाने पर करदाता को पेनल्टी का भुगतान करना होता है. किंतु वित्त वर्ष समाप्ति के सवा तीन माह बाद भी विवरणी एवं ऑडिट के प्रारूप केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा ई-फाईलिंग वेबसाईट पर अपलोड नही किए गए है यदि अभी भी प्रारूप ई-फाईलिंग वेबसाईट पर अपलोड कर दिए जाते है तो करदाता को मात्र 2 माह का ही समय मिलेगा. जबकि पूर्व वित्त वर्षों में उसे अप्रैल से जुलाई तक अर्थात् 4 माह का समय मिलता था इसी तरह ऑडिट की पात्रता वाले करदाता को भी अब मात्र 3 माह का ही समय मिलेगा. वित वर्ष 2024-25 के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा विवरणी प्रस्तुती हेतु विस्तृत जानकारियां चाही गई है ऐसी स्थिती में इतने कम समय मे करदाता एवं कर सलाहकारों तथा सी.ए. से जुड़े हुए प्रोफेशनल व्यक्तियों को समय कम मिलने के कारण अत्यधिक परेशानी उठाना पड़ेगी.

पेज एक का शेष

लुधियाना में मिला 15600 करोड़ का निवेश

मप्र में लगाएं साइकिल बनाने की फैक्ट्री: मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में स्कूली बच्चों को साइकिलें बांटी जा रही हैं. साइकिलें मुख्यत:पंजाब में ही बनती हैं. यही साइकल मप्र में भी बन सकती हैं. उद्योगपति मध्यप्रदेश में साइकल बनाने की फैक्ट्री लगाएं. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सोने की चिड़िया की पहचान रखता था. वर्ष 1947 में देश आजाद हुआ, तब भारत दुनिया की 15वीं अर्थ-व्यवस्था हुआ करता था. इजरायल और जापान जैसे देश कहां से कहां पहुंच गए. वर्ष 2014 में भारत 11वें स्थान पर था और आज बदलते दौर में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थ-व्यवस्था बन गया है और अब तीसरी अर्थ-व्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विभिन्न उद्योगपतियों द्वारा प्रदेश में निवेश हेतु 15,606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे लगभग 20,275 से अधिक रोजगार सृजन की संभावना है.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7390/60